

18/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाच उप। बहस उभयपक्ष
 खुली गई। जर्गी अधिकार का बहस में
 जर्गी पत्र के तथ्यों को देखते हुए निवेदन
 किया कि ग्राम कोठा तहसील फतेहगढ़ जिला
 जैलमैर के समरी खसरा नम्बर 71 व 72
 खसरा अन्दाजीचा 172.10 बीघा वर्तमान बहस
 सं. 781 खसरा 5.8329 है. एवं खस. 516 खसरा 9.4168 है.

सिवायचक भूमि में जर्गीदारी घोषणा हेतु एक वाद
 सं. उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पेश किया है।
 समरी में अन्दाजीचा दर्ज खसरा को ख्याती
 बंदोबस्त में काटकर सिवायचक दर्ज किया।
 वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के विपरीत
 हस्तक्षेप न करें।

जवाब में तहसीलदार फतेहगढ़ ने जर्गी द्वारा
 वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन
 किया कि वादग्रस्त आराजी प्रथम बन्दोबस्त
 से आदिनाब तक सिवायचक दर्ज है और
 उपर्युक्त का कोई कब्जापत्र नही दस्तावेज
 इसलिए मामला प्रथम दृष्टया जर्गी के पक्ष में नही है।
 साथ ही ~~अपक्ष~~ बहस में निवेदन किया कि
 जर्गी समरी सेटलमेंट में अंदाजीचा तरीके
 से उपर्युक्त का नाम दर्ज था जिसे जिले के
 कोई नक्शे नही बने कोई वास्तविक पैमाईश
 नही हुई। बाद में उपबन्ध विभाग ने



स्पार्डि सेटलमेंट के समय मीके पर काबिज
 काश्त खानेदारों के खयरो की पैमाइश कर
 कब्जा जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था
 उन्हे खानेदारी दर्ज किया था। शीक भूमि
 को सही तरीके से आराजी राज दर्ज किया
 था। साथ ही यदि जर्मीगण को इस
 संबन्ध में आपत्ति थी और गलत दर्ज
 किया गया था तो उस संबन्ध में कोई
 अपील रूब में नहीं की गई थी जिससे
 साबित होता है कि जर्मीगण कभी कब्जा
 काश्त नहीं रहे एवं गलत दर्ज नहीं
 किया गया। अतः जर्मीगण का हक
 वादग्रस्त आराजी पर हक हबुब नहीं
 होने से जर्मीगण का जर्मीना पर खारिज
 फरमाया जावे।

उन्मयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली
 में फस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त
 आराजी प्रथम स्पार्डि बन्दोबस्त से आडिवांकु
 तक लिवायचक दर्ज है अतः मामला प्रथम
 दृष्टया जर्मीगण के पक्ष में नहीं है। जर्मीगण
 द्वारा प्रथम स्पार्डि बन्दोबस्त में पैमाइश एवं
 तब्शा निर्माण प्रक्रिया एवं आपत्ति निस्तारण
 प्रक्रिया में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की इस
 सम्बन्ध में कोई फस्तावेज पेश नहीं किया है



न ही रूप में बंदोबस्त कार्रवाई के विरुद्ध अपील दर्ज की करवाई हो के इस्तख्ज पेश ~~किये~~ नहीं किये। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रयोग के पक्ष में साबित नहीं होता है।

व्यक्त वादग्रस्त आराजी खिलायत दर्ज होने, कोई अपील पेश नहीं करने एवं केवल समरी में अंदाजिया रिकॉर्ड के आधार पर अर्थात् निषेधाज्ञा का प्रथम पत्र पेश करना समरी के अंदाजिया रिकॉर्ड की आड़ में मूल्यवान सरकारी जमीन पर एक * जवाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अर्थात् बंदोबस्त के बाद अदिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कारत के सम्बन्ध में भी इस्ताख्जी लाइय प्रयोग द्वारा पेश नहीं किये गये। अतः अपूर्णता अति का विरुद्ध भी प्रयोग के पक्ष में नहीं ~~साबित~~ होता है।

निष्कर्षतः प्रथम दुख्या मामला, सुविधा



का संतुलन एवं अपूर्णता अति के सभी विरुद्ध प्रयोग के विरुद्ध होने से प्रथम पत्र खारिज किया जाकर फैसल नुमा है। यह निर्णय मेरे हस्ताक्षर के आज दिनांक 18.03.25 को जारी होकर पुणे न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कमिश्नर एवं उप खण्ड अधिकारी फतेहगढ़ जैमलमेर